

“सहयोग, समन्वय और समेकन के आधार पर भारत-बांग्लादेश संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है।”

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 3-6 अक्टूबर को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगी, जो बांग्लादेश में आम चुनाव (दिसंबर 2018) और भारत (मई 2019) में आम चुनाव के बाद शेख हसीना की भारत की यह पहली यात्रा होगी। वह द्विपक्षीय दौर के बाद विश्व आर्थिक मंच की ओर से आयोजित भारत आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगी। भारत और बांग्लादेश आज कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के साथ, आगे बढ़ रहे हैं।

लाभ के बावजूद विवादित मुद्दे:-

वर्तमान बांग्लादेश सरकार ने भारत के खिलाफ सुरक्षा खतरों और विद्रोह के मुद्दों को हटा दिया है और आज भारत-बांग्लादेश सीमा भारत का सबसे सुरक्षित सीमा क्षेत्र है। 2015 में भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर एक मील का पत्थर साबित हुआ, जहां दोनों पड़ोसियों ने एक असें से लंबित मुद्दे को हल किया था।

वित्त वर्ष 2017-18 में द्विपक्षीय व्यापार 9 बिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक था और वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 1.25 बिलियन डॉलर तक पहुंचकर बांग्लादेशी निर्यात 42.91% तक बढ़ा है। गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने से बांग्लादेशी निर्यात को मदद मिलेगी। 2018 में, बांग्लादेश द्वारा आयातित 660 मेगावाट बिजली के अलावा, बिजली के भारतीय निर्यात में 500 मेगावाट की वृद्धि हुई। पावर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ 1,600 मेगावाट का पावर स्टेशन विकसित किया जा रहा है।

हवाई यात्रा पर भूमि मार्गों ने लोकप्रियता हासिल की है और भारत आने वाले 85.6% बांग्लादेशियों द्वारा इसे पसंद किया जा रहा है। ढाका-कोलकाता और कोलकाता-खुलना पर ट्रेन सेवाएं अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं, जबकि अगरतला-अखौरा मार्ग पर एक तिहाई कार्य निर्माणाधीन है।

2018 में पांच अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू की गईं; साथ ही इस साल मार्च में, पहली बार ढाका-कोलकाता क्रूज जहाज सेवा लॉन्च की गई। 2018 में भारत आने वाले बांग्लादेशी पर्यटकों का कुल प्रतिशत 21.6% (जिसमें से 83.7% पर्यटक और 10.28% रोगी) था। वर्तमान में बांग्लादेश, भारत के स्वास्थ्य पर्यटन राजस्व में 50% योगदान देता है।

कुछ प्रमुख बकाया मुद्दे अभी भी बने हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक तीस्ता जल बंटवारा समझौता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सहमत जल-बंटवारे की शर्तों का समर्थन करने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप गतिरोध पैदा हो गया। पानी की कमी से 1,00,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है, जिसमें प्रदूषण मिट्टी को प्रभावित करता है; कीटनाशकों और सिंचाई की बढ़ती लागत ने खेती को कम लाभदायक बना दिया है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की सूची में से 19 लाख असमियों को यह कहकर बाहर निकाल दिया गया है कि वे 1971 के बाद से 'बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों' के रूप में असम में रह रहे थे। बांग्लादेश अपने रुख पर कायम है कि 1971 के युद्ध के दौरान कोई भी प्रवासी अवैध रूप से असम की यात्रा नहीं करता था, इसके बाद से यह विवाद NRC संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है।

सीमा पर होने वाली हत्याएं कम हुई हैं। भारत की सीमा सुरक्षा बल (BSF) का दावा है कि पशु तस्करी से निपटने में अधि कांश गोलीबारी आत्मरक्षा में होती है। हालाँकि, भारत द्वारा मवेशियों के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद से, पशु व्यापार 2013 में 23 लाख से गिरकर इस वर्ष मई के अंत तक 75,000 तक पहुंच गया है, जो सेना के तर्क को असंबद्ध बनाता है।

संबंधों के अंतर्राष्ट्रीय नियमों में कहा गया है कि सैन्य कार्रवाई 'उकसावे के समानुपाती' होनी चाहिए, जो इस तरह की हत्याओं को मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बनाती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में, बीएसएफ महानिदेशक ने कहा था: भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध और दो सीमा रक्षक बल इस समय अपने संबंध के सबसे अच्छे दौर में हैं।

2010 से, भारत ने विकास परियोजनाओं को वित्त देने के लिए बांग्लादेश को 7.362 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है, जिसे तीन चरणों में पूरा किया जायेगा। लालफीताशाही के कारण, दिसंबर 2018 तक सिर्फ 442 मिलियन डॉलर का वितरण किया जा सका है। जहाँ एक तरफ बांग्लादेश कार्यान्वयन में धीमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की छूट प्रक्रिया को भारत के एक्जिम बैंक द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता ने भी कोई मदद नहीं की है। 2017 में शेख हसीना की दिल्ली यात्रा के दौरान, दो रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2018 में, भारत ने हथियार खरीदने के लिए 500 मिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया था तथा नौसेना बलों के बीच सहयोग के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

रोहिंग्या का विषय

रोहिंग्या का मुद्दा और इस मुद्दे पर 2017 में भारत की टिप्पणी बांग्लादेश के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि बांग्लादेश दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य शासन में शामिल भारत से एक लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को उत्पीड़न से बचने के लिए आश्रय प्रदान करने की चुनौती का सामना कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर (अगस्त 19-21) द्वारा ढाका की हालिया यात्रा ने भारत की स्थिति में एक उल्लेखनीय पड़ाव देखा; उन्होंने तब कहा था: 'हम इस बात से सहमत हैं कि बिस्थापितों (रोहिंग्या) की सुरक्षित, त्वरित और स्थायी वापसी तीनों देशों - बांग्लादेश, म्यांमार और भारत - के राष्ट्रीय हित में शामिल है।'

भारत-बांग्लादेश संबंध पिछले दशक में सहयोग के कई क्षेत्रों में विकास के साथ परिपक्व हुए हैं। एक ऐसे पड़ोस में जहां अविश्वास और निराशावाद दोस्ती और उम्मीद पर कायम है, दोनों देशों के रिश्तों ने आशावाद की उम्मीद जगाई है। लेकिन जितनी जल्दी मौजूदा चुनौतियां हल होंगी, उतना ही दोनों देशों के लिए बेहतर होगा पिछले महीने के अंत में 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर, श्री मोदी ने शेख हसीना को आश्वासन दिया था कि उन्हें NRC और जल-बंटवारे के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे हैं।

साझा औपनिवेशिक विरासत, इतिहास और सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों की मांग है कि दोनों देशों का राजनीतिक नेतृत्व भारत-बांग्लादेश संबंधों में गति प्रदान करे। शेख हसीना की भारत यात्रा से उम्मीद है कि दोनों देश सहयोग, समन्वय और समेकन के माध्यम से इस रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाएंगे।

भारत-बांग्लादेश संबंध

चर्चा में क्यों?

- बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 3-6 अक्टूबर से चार दिवसीय यात्रा पर भारत जाएंगी, जहाँ वह भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगी।
- इस दौरान दोनों देशों के बीच करीब एक दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद है। भारत और बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के बाद हसीना की भारत की यह पहली यात्रा होगी।
- शेख हसीना और मोदी पांच अक्टूबर को द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वह तीन और चार अक्टूबर को विश्व आर्थिक मंच की ओर से आयोजित भारत आर्थिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगी।
- तीन-चार अक्टूबर को नई दिल्ली में होने जा रहे इस सम्मेलन में भारत सहित 40 देशों के 800 से ज्यादा नीति निर्माता, कंपनी जगत की शीर्ष हस्तियाँ और विशेषज्ञ भाग लेंगे।
- दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े एक दर्जन द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद है और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच तीस्ता समेत साझा नदियों के जल बंटवारे के मुद्दे की समीक्षा और रोहिंग्या संकट के मुद्दे पर चर्चा की भी संभावना है।

भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व

- बांग्लादेश दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ जुड़ने के लिए भारत की योजना है, साथ ही साथ भूमि से जुड़े पूर्वोत्तर को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत की योजना दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाने की है, जिसने दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को प्रभावित करते हुए बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है।
- भारत की पहली पड़ोस नीति ने बांग्लादेश पर ध्यान केंद्रित किया है, जो भारत की एकट ईस्ट पॉलिसी और BIMSTEC (बंगाल की खाड़ी में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए पहल) और BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) जैसी उप-क्षेत्रीय समूहों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पृष्ठभूमि

- भारत पहला देश था जिसने दिसंबर 1971 में अपनी आजादी के तुरंत बाद बांग्लादेश को एक अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- भारत और बांग्लादेश 4000 कि.मी. से अधिक की सीमा साझा करते हैं, जो कि भारत की किसी भी पड़ोसी के साथ साझा की जाने वाली सबसे लंबी भूमि सीमा है।

सुरक्षा और सीमा प्रबंधन

- सीमा-पार से गैरकानूनी गतिविधियों और अपराधों की जाँच के लिए और भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ शांति के लिए सीमा सुरक्षा बलों की सहायता के लिए 2011 में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (CBMP) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- पावर प्रोजेक्ट्स: भारत बांग्लादेश में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए लगभग 1100 मेगावॉट बिजली निर्यात करने के लिए तैयार है। 3600 मेगावॉट से अधिक की बिजली परियोजनाएं भारतीय कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।
- रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में निर्माण की शुरुआत के साथ भारत बांग्लादेश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भी भागीदार है।
- 2017 में, बिजली और ऊर्जा क्षेत्रों में लगभग 10 बिलियन डॉलर के 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

व्यापार संबंध

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका वार्षिक कारोबार लगभग 9 बिलियन डॉलर से अधिक है और अनुमानित अनौपचारिक व्यापार लगभग 8-9 बिलियन डॉलर है।
- बांग्लादेश में भारतीय निवेश 3 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। भारत में बांग्लादेशी निर्यात के प्रवाह को सक्षम करने के लिए, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के तहत 2011 में ड्यूटी-फ्री एंटी दी गई थी।

नदी के पानी का बँटवारा

- भारत और बांग्लादेश 54 आम नदियाँ साझा करते हैं। एक द्विपक्षीय संयुक्त नदियों आयोग (JRC) आम नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम करने के लिए दोनों देशों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए जून 1972 से काम कर रहा है।

संपर्क

- अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन पर प्रोटोकॉल (PIWTT) 1972 के बाद से परिचालन कर रहा है जो बांग्लादेश के नदी प्रणालियों के माध्यम से आठ विशिष्ट मार्गों पर भारत से जहाजों पर माल की आवाजाही की अनुमति देता है।
- इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच हवाई, रेल और बस कनेक्टिविटी भी है।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

- भारत बांग्लादेश के अधिकारियों/नागरिकों के लिए कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका, परमाणु वैज्ञानिक, शिक्षक आदि शामिल हैं।
- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण द्विपक्षीय संबंधों और लोगों से लोगों के बीच संपर्क में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत-बांग्लादेश के संबंधों में सहयोग, समन्वय और समेकन के बाद आए बदलावों पर विचार कीजिए-
 1. 2016 में भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब भारत-बांग्लादेश सीमा भारत का सबसे असुरक्षित सीमा क्षेत्र बन गया है।
 2. गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने से बांग्लादेशी निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।
 3. वर्तमान में बांग्लादेश, भारत के स्वास्थ्य पर्यटन राजस्व में 50% योगदान देता है।उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सत्य हैं?
 - (a) 1 और 3
 - (b) 1 और 2
 - (c) 2 और 3
 - (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the changes after cooperation, coordination and consolidation in Indo-Bangladesh relations-
 1. The Indo-Bangladesh border has now become the most unsafe border area in India after the signing of the Land Boundary Agreement in 2016.
 2. Removing non-tariff barriers will encourage Bangladeshi exports.
 3. Currently, Bangladesh contributes 50% to India's health tourism revenue.Which of the above statements is/are correct?
 - (a) 1 and 3
 - (b) 1 and 2
 - (c) 2 and 3
 - (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'शेख हसीना सरकार के कार्यकाल में भारत-बांग्लादेश संबंध सबसे बेहतर दौर में हैं, हालांकि कुछ मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।' इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? अपने मत के समर्थन में तर्क भी प्रस्तुत कीजिए।

'India-Bangladesh relations are in the best phase under the tenure of Sheikh Hasina, although some issues need to be addressed.' To what extent do you agree with this statement? Also present an argument in support of your opinion.

(250 Words)

नोट : 1 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।